(xi) Medicinal Plants Cultivation of Legums Food Processing Ringal, Agro-Forestry, Cold Water Fisheries, Community Economic Tourism, Essential Oil Distribution and Polyhouse Vegetables Cultivation	Pithoragarh (Uttar Pradesh)
(xii) Horticulture (Organic Vegetable Cultivation and Trading, Potato Seed Multiplication) Poultry and Wasteland Development)	Jabalpur (Madhya Pradesh)
(xiii) Vegetable, Flower Seed production, Acquaculture, Irrigation & Water-Management, Soil Conservation, Land Development Sericulture, Live-stock, Non-Farm Sector, Agro-processing Wasterland Development, Agro-forestry Marketing, Storage and Export on Commercial lines.	Pune (Maharashtra)

2. **Projects implemented:**

(i) An Agri-Business Information Centre has been set up at Chandigarh in association with Punjab Agro Industries Corporation.	(Pun
(ii) SFAC Kerala has been given 50.00 lakhs grant with which they are assisting Small farmers for value addition in their hands by taking up coconut wood and 'pandanus' based activities.	(Kerala)

Target for Rice and Wheat Production

2639. SHRI ANANTA SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the target fixed for the production of rice and wheat during 1996-97, 1997-98 and 1998-99; and

(b) the year-wise details thereof alongwith steps taken to increase the production of rice during 1999-2000 and also in the remaining years of Ninth Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The target fixed for the production of rice and wheat during the years 1996-97, 1997-98 and 1998-99 were as follows:

(Million tonnes)

Year	Rice	Wheat
1996-97	81.00	65.00
1997-98	83.00	68.50
1998-99	84.20	70.00

For increasing the production of rice during 1999-2000 and also in the remaining years of Ninth Plan, a Centrally Sponsored Integrated Cereals Development Programme in Rice Based Cropping Systems Areas (ICDP-Rice) will be implemented in 17 major rice producing States/UT. Incentive are proposed to be provided on transfer of technologies through demonstrations and farmers' trainings. Assistance on use of certified seeds and selective mechanisation like power tillers etc. will also be provided under the programme.

गन्ने के उत्पादन के लिए योजनाएं

2640. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामुवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने और इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए एक योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु देश के कुछेक जिलों का चयन किया है, यदि हां, तो चयनित जिलों के नाम क्या हैं और उनके चयन का आधार क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी, हां। गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के सतत विकास से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अधिक पैदावार देने वाली किस्मों सहित विकसित प्रौद्योगिकी को प्रदर्शनों व कृषक प्रशिक्षण के द्वारा किसानों को अन्तरित किया जा रहा है। इसके अलावा बीज, फार्म, उपस्करों, ड्रिप सिंचाई, ऊष्मा-उपचार संयंत्रों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण आदानों तथा ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि के लिये भी सहायता दी जाती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि करने तथा इस प्रकार, कृषि की लागत में कमी लाने में मदद मिलती है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अलावा, खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के चीनी विकास कोष से उदार ऋण प्रदान करके मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के सतत विकास से संबंधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये जिलों की पहचान राज्य/राष्ट्रीय स्तर से कम उत्पादकता के आधार पर की जाती है। जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास के अंतर्गत अभिज्ञात किये गये जिलों के नाम।

1. आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, विजियानग्राम, विशाखापट्टनम, प्रकाशम, नेलोर, करीमनगर, गुंटुर, मेहबूब नगर, नालगोनियाखम्मम
2. बिहार	पटना, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, रोहताश, गया, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय, सारण, सिवान, मधुबनी, गोपालगंज, चम्पारण (पूर्व), चम्पारण (पश्चिम), समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, हजारीबाग, पलामू
3. गुजरात	भरूच, साबरकांठा, बड़ोदरा, बासाकांठा, कुचवालसाड, जूनागढ़, राजकोट, औरैली
4. हरियाणा	अम्बाला, जिंद, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, भिवानी, कैथल, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत
5. केरल	अलापुजा, पल्लकाड, इदुकी
6. कर्नाटक	बेलगाम, बिदर, बेलरी, कोलार, गुलबार्गा, धारवाड़, दक्षिण कन्नड़
7. मध्य प्रदेश	मण्डला, नरसिमपुर, बालाघाट, बेतुल, छिन्दवाड़ा, मोरेना, बिलासपुर, ग्वालियर, राजगढ़, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, देवास, इन्दौर, पश्चिम निमार (खरगांव), धार, दतियां, टीकमगढ़, सेहोर
8. महाराष्ट्र	धुले, जलगांव, परभानी, सोलापुर, नांदेड़, सतारा, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, लातुर, अकोला, बुलधाना, येवातमल, भान्द्रा, अमरावती
9. उड़ीसा	बालासोर, कालाहांडी, कोरापुट, कूनझार, फुलबनी, मयुरभंज, सुन्दरगढ़
10. पंजाब	होशियारपुर, लुधियाना, अमृतसर, गुरुदासपुर, रोपड़, संगरूर, पटियाला, जालन्धर, भटिंडा, फरीदकोट

11. असम	गचर/सिल्चर, करीमगंज, सुनौतपुर, नौगांव, जोरहाट, सिबासंगार, डिबरूगढ़, गोलाघाट
12. मणिपुर	इम्फाल
13. मिजोरम	कालासिब
14. नागालैंड	दीमापुर
15. गोवा	गोवा
16. राजस्थान	बंसवाड़ा, बुन्दी, चित्तौरगढ़, गंगानगर, उदयपुर, डुंगरपुर
17. तमिलनाडु	उत्तरी आरकौट, दक्षिणी आरकौट, धर्मपुरी, सम्बुवरयुर, चेंगलअन्नी, कन्याजर, मदुरै, कोयंबटूर
18. त्रिपुरा	अगरतला
19. उत्तर प्रदेश	हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, पिलीभीत, फर्रुखाबाद, बिजनौर, इटावा, मुरादाबाद, कानपुर, रामपुर, फतेहपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, जालौन, गाजीपुर, हमीरपुर, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, खीरी, हरदोई, फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच, बाराबंकी, नैनीताल, सहारनपुर
20. पश्चिम बंगाल	मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, बर्दवान, बीरभूम, पुरूलिया, मिदनापुर (पश्चिम)
21. पांडिचेरी	पांडिचेरी

खाद्यान्न उत्पादन का आकलन

2641. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने वर्ष 1998-99 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में पृथक-पृथक आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा आकलित मात्रा का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मात्रा के भिन्न-भिन्न आकलन के क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय देश में खाद्यान्न उत्पादन का कोई स्वतंत्र आकलन नहीं करता है। कृषि सांख्यिकी के मंडल संगठन कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये फसल उत्पादन संबंधी आकलन वित्त मंत्रालय द्वारा 'आर्थिक सर्वेक्षण' तैयार करने में उपयोग में लाये जाते हैं।

कृषि मंत्रालय ने राज्यों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त रबी फसलों में बुवाई की प्रगति की प्रवृत्ति तथा खरीफ फसलों के अग्रिम अनुमानों के आधार पर 30.1.99 को 195.25 मिलियन मी॰ टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान बनाया है। इसे वित्त मंत्रालय को 1998-99 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया था। तथापि, 22-23 मार्च, 1999 को आयोजित 'खरीफ अभियान, 1999 संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन' में राज्य सरकारों द्वारा दी गई अद्यतन जानकारी के आधार पर खाद्यान्न उत्पादन के पूर्वतर आकलन में वृद्धित संशोधन करते हुए इसे 200.88 मिलियन मी॰ टन कर दिया गया था।

विभिन्न फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमानों में संशोधन कृषि मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष में 4 बार किया जाता है।

Modified Crop Insurance Scheme

2642. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

-(a) whether the modified Crop Insurance Scheme prepared by a core group has since been finalised;